श्री रामानन्द यादव : दूसरा सवाल यह है कि टेल एण्ड में, पांच किलोमीटर के एरिया में जिनकी धान की खेती पटती नहीं है, उनसे रेंट वसूलने में क्या सरकार माफी देगी ?

श्री सभापति : बगैर पानी दिये क्यों महसूल लेती है ।

SHRI RAM NIWAS MIRDHA; First of all, I would like again to reiterate that the Bansagar Agreement would not come in the w'ay of Sone Canal system. As a matter of fact, it will stabilise the system.

श्री रामानन्द यादव : उसमें तो हम लोगों को कहां वाटर मिलेगा । पहले जितना मिलता था, उसमें उतना पानी नहीं आएगा । बाण सागर के एग्रीमेंट में सीधा है कि हमको इतना मिलेगा, मध्य प्रदेश को इतना मिलेगा । उसके बनने से अभी जितना मिल रहा है, उससे भी कम मिलेगा ।

श्री सभापति : पहले बनने तो दीजिए ।

SHRI RAM NIWAS MIRDHA: Sir, the total water availability io the Sone basin at 75 per cent dependability comes to 14.25 acre feet, and under the inter-State Agreement the shares of various States are as under;

Madhya Pradesh—5.25 million acre feet.

U.P. —1.25 million acre feet.

Bihar —7.5 million acre- feet.

श्री रामानन्द यादव : पहले कितना मिला था हम लोगों को ?

SHRI RAM NIWAS MIRDHA: This would increase in a way, it is expected to increase, the supply in the system, and, if nothing else, at least to stabilise it. As regards dredging, this 'has been discussed in this House before also and I have said we have consulted experts on this problem on a number of occasions and it is their opinion, a considered opinion, that dredging of big rivers.. .

MR. CHAIRMAN: Canals.

SHRI RAM NIWAS MIRDHA: These are very big canals and canals are dredged as a part of their own annual maintenance. It is true that maintenance of some of the canal systems may not be up to the standard. But to have a programme of dredging rivers or big canals us such has not been found to be viable from the technical as well as economic angles.

श्री सभापति : लास्ट, पानी तो दिया नहीं लेकिन महसूल लेते हैं ।

SHRI RAM NIWAS MIRDHA: That is obviously the concern of the State Government and I don't think you would wish we interfere with it in (ha way.

Flood control department of Delhi Administration

*43. SHRI RAM BHAGAT PASWAN: Will the Minister of IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that payment to the works done by the Mechanical Division of the Flood Control Department of the Delhi Administration is made on hire basis and no assessment is made for the work done by the machine;

(b) whether it is also a fact that private contractors are awarded works instead; and

(c) if so, what are the details ki this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF IRRIGATION (SHRI RAM NIWAS MIRDHA) (a) Delhi Administration has informed that for the use on departmental works of the machinery, which are operated and maintained by the Mechanical Divisions of the Flood Control Department of Delhi Ad-l ministration, payment is made to the

Mechanical Divisions on the basis of hours of their use on the works at a specified hourly rate. The work done by these machines is also measured on the basis of cross-sections.

(b) and (c) Delhi Administration has further informed that in order to complete the work expeditiously the earthwork is being executed both through contractors and also by the departmental machines according to the site conditions in different reaches. Important schemes on which works ace in progress are:

1. Increasing the capacity of Najafgarh drain.
2. Re-modelling of Nangloi drain.
3. Construction of Supplementary drain.
4. Construction of Shahdara drainage scheme.
5. Construction of laitpur drain.

श्री रामभगत पासवान : सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने अपने जवाब में कहा है कि कार्य को जल्द पूरा करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में स्थल परिस्थितियों के अनुसार ठेकेदारों के माध्यम से तथा विभागीय मशीनों के द्वारा भी मिट्टी कार्य किया जा रहा है। तो मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि मशीन से जो कार्य किया जाता है उसका रेट और ठेकेदारों के माध्यम से जो कार्य किया जाता है उसका रेट क्या है ? क्या यह सही है कि मशीन द्वारा जो कार्य किया जाता है जिस को उसी रेट से नापा जाता है जिस रेट से ठेकेदारों द्वारा किया जाता है ? दूसरे जब मशीन उनके पास उपलब्ध है तो क्यों मशीन के द्वारा 20 परसेंट ही कार्य होता है, फ्लड कण्ट्रोल का जब जल्दी कार्य कराना है और ठेकेदारों के द्वारा 80 प्रतिशत होता है, क्या चीफ इंजीनियर फ्लड कण्ट्रोल का मोटीवेशन नहीं रहता कि वे अधिक से अधिक कार्य ठेकेदारों के माध्यम से कराए जिससे उन का परसेंटेज अधिक हो ?

श्री रामनिवास मिर्धा : श्रीमन्, यह सही है कि इसमें कुछ काम मिट्टी खोदने इत्यादि का मशीनों द्वारा भी किया जाता है और प्राइवेट जो ठेकेदार हैं उनकी मार्फत किया जाता है। ऐसा अन्दाजा लगाया गया है कि जो मशीनों से काम होता है वह कुछ मंहगा पड़ता है इसलिए उनका उपयोग उसी जगह किया जाता है जहां पर मैनुअल लेबर को काम करने में असुविधा हो या जहां नहर और नीचे चली गयी हो या जहां पानी आदि में कीचड़ मिल गया हो और आदमी वहां काम न कर सकते हों। इसलिये पहली बात तो यह कि मशीनों का उपयोग किया जाता है उन रीचेज में जहां आवश्यक है और मशीन और आदमी दोनों मिल कर इस काम को करने में लगे हुए हैं।

श्री राम भगत पासवान : क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि फ्लड कन्ट्रोल की कितनी योजनाएं हैं जिनमें काम मशीनों द्वारा किया जानेवाला था लेकिन करा दिया गया ठेकेदार के माध्यम से ? दूसरे बेसापार और खयालापार, इन दोनों जगहों पर पहले ठेकेदार लगाये गये थे और ठेकेदारों को पेमेंट कर दिया गया और बाद में मशीनों द्वारा काम कराया जा रहा है। तो इस योजना में आप का कितना खर्च हुआ है और विभिन्न योजनाएं जो चल रही हैं उन में टोटल खर्च कितना हुआ है और ठेकेदारों द्वारा कितना काम हुआ है और मशीनों द्वारा कितना काम हुआ है और उनके लिये अलग-अलग कितना-कितना एमाउन्ट खर्च हुआ है ? और तीसरे मेरा सवाल है कि क्या यह सही है कि मशीने उपलब्ध रहते हुये भी यह कहा गया है कि मशीन की हालात खराब है और इसलिये मैनुअल लेबर लगाया गया है

और उसके द्वारा काम कराया जाता है जहां मिक्स्ड काम हुआ है ठेकेदारों और मशीनों दोनों के द्वारा वहां क्या आप इसकी जांच करायेंगे?

श्री रामनिवास मिर्धा : पहले तो मैं यह निवेदन करूंगा कि सारा काम एक जगह नहीं होता। कुछ क्षेत्र दे दिया जाता है कि जहां ठेकेदार काम करते हैं और दूसरे किसी क्षेत्र में मशीनें काम करती हैं और सरकारी तरीके से वहां काम होता है। मैं रेट बता देता हूं। जहां मैनुअल लेबर काम करता है ढाई अर्थ पर वहां 6 से 7 रुपये परक्यूबिक मीटर का रेट होता है और नीचे जब खुदाई होती है जहां पानी आ जाता है जमीन में तो उसके बाद रेट होता है 13 रुपये प्रति क्यूबिक मीटर के हिसाब से और मशीन का रेट जो आंका गया है वह 15.4 रुपए प्रति क्यूबिक मीटर का है। तो इसलिए सब जगहों पर मशीन का इस्तेमाल करना उचित नहीं समझा गया और मशीन का प्रयोग वहीं किया जाता है कि जहां पर मैनुअल लेबर को काम करने में असुविधा हो या वह काम न कर सकते हों। और यह कहना ठीक नहीं है कि ठेकेदारों को काम वहीं दिया जाता है कि जहां काम आसान होता है या जो ओदी जगहें होती हैं। और इस काम के लिए कितना-कितना एमाउन्ट खर्च किया गया अलग-अलग यह बताना मेरे लिए अभी संभव नहीं है।

श्री राम भगत पासवान : मैं यह जानना चाहता हूं कि अभी तक कितना काम ठेकेदारों के माध्यम से हुआ है। चूंकि मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि अभी तक कितना काम मशीन के द्वारा हुआ है और कितना ठेकेदारों के द्वारा हुआ है और उन पर अलग-अलग कितना एमाउन्ट आप ने खर्च किया है?

SHRI RAM NIWAS MIRDHA; Sir, I will readily concede that because of the difference in rates more work is done by manual labour, which means more or less by the contractors, and I cannot give-the figures but it is more than what is being done by the machines.

श्री जे० के० जैन : सभापति महोदय, 1977 में जो दिल्ली में बाढ़ आई थी उसको अभी तक लोग भूले नहीं हैं कि उस में किसी तरह से पोश कालोनीज भी 12, 12 फीट पानी में डूब गयीं थी और सारे दिल्ली में पानी भर गया था। जो मेरी जानकारी है वह यह कि आज कारपोरेशन के पास पैसा नहीं है कि जिस से वह आने वाले किसी फ्लड का मुकाबला करने का इंतजाम कर सके। तो मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ ऐसी हिदायतें दी हैं कि वह कारपोरेशन से पैसा मुहैय्या करे और क्या दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के पास इतना पैसा है कि जिससे वह दिल्ली में जून के अंत में जो बारिश होती है उस के फ्लड से दिल्ली को बचा सके?

श्री रामनिवास मिर्धा : माननीय सदस्य का यह कहना उचित है कि 1977 में बहुत भयंकर बाढ़ यहां आयी थी और उस बाढ़ का अनुभव देखते हुए दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा के प्रतिनिधियों ने मिलकर एक मास्टर प्लान बनाया कि साहबी नदी को किस प्रकार रोका जाए। हरियाणा में क्या-क्या कार्य हो और राजस्थान में क्या-क्या हो और दिल्ली में क्या-क्या हो। इस योजना में जहां तक दिल्ली का संबंध है, दो, तीन भाग हैं। पहला भाग तो है कि नजफगढ़ के ड्रेन को बढ़ाया जा रहा

रहा है और दूसरा है कि एक सप्लीमेंटरी ड्रेन 5000 क्यूसेक्स का और बनाया जाय और नजफगढ़ का ड्रेन जिसकी क्षमता 3000 थी उसे 8 और 10 हजार क्यूसेक्स तक बढ़ाया गया है और वह संपूर्ण होने जा रहा है। लेकिन जहां तक सप्लीमेंटरी ड्रेन का संबंध है दिल्ली प्रशासन का यह कहना है कि उनको जमीन एक्वायर करने में या और काम करने में कुछ दिक्कतें आ रही है और वह पैसे के अभाव से नहीं बल्कि और वजूहात के कारण से वह काम तेजी से नहीं कर पा रहा है जितनी कि तेजी से वह काम करना चाहते हैं । हमने उनको कई दफा यह निवेदन किया कि बाढ़ कभी भी आ सकती है, भयंकर रूप से भी आ सकती है । इसलिए जो भी 1979 में समझौता हुआ था उसके अन्तर्गत एक सप्लीमेंट्री ड्रैन बनाये और जो भी हो करें ।

जहां तक धनाभाव का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि वह स्थिति नहीं है और अगर होगी तो केन्द्र सरकार उस पर विचार करेगी ।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : श्रीमन, मैं मंत्री जी से ठोस बात जानना चाहता हूं एक तो मास्टर प्लान बाढ़ रोकने के लिए, बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए 1979 में बना और आज 1984 का चौथा महीना चल रहा है और दो तीन महीने बाद बाढ़ का मौसम फिर आ सकता है और वह 1977 का रूप ले सकती है । तो इस योजना को कहां तक पूरा करने के लिए आप काम कर पाये हैं ।

दूसरे, अभी हमारे प्रश्न कर्ता का प्रश्न था कि वहां मशीन की अपेक्षा कान्ट्रेक्ट लेबर से ज्यादा काम लिया जा रहा है । मैं समझता हूं कि मशीन सरकार को होगी जो कि सरकारी मशीनरी को पैसा नहीं दे सकती और कांट्रेक्टर जो है वह सरकारी यंत्र या तंत्र को पैसा प्रदान कर सकता है । तो क्या मुख्य कारण यह नहीं है कि मशीन का अधिक उपयोग नहीं हो रहा है ? यदि मशीन का उपयोग अधिकतम होता तो काम भी अधिक होता, सफाई के साथ भी होगा लेकिन उसको न करके कांट्रेक्टर्स से काम लिया जा रहा है इसलिए कि सरकारी मशीनरी को वह ऊपर से भी पैसा दे सकता है ? यही कारण है जिसको छिपाने की कोशिश की जा रही है ।

श्री सभापति : उनका रेट सस्ता है । उसमें 13 और 15 का फर्क है ।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : जी नहीं रिपोर्ट देने वाली जो मशीनरी है वह मशीनरी वही है जो कांट्रेक्टर को पैसा देती है । मशीन का काम इतना रिफाइन है कि उसका 15 का रेट भी हो तो भी कांट्रेक्ट लेबर से वह सस्ता पड़ेगा । जो 13 और 15 का फर्क है वह उसकी गुणवता के अनुसार देखा जाना चाहिए । अगर उसकी तुलना की जाएगी तो पता लगेगा कि मशीन का काम अच्छा है लेकिन मशीन सरकार के द्वारा चल रही है इसलिए वह सरकारी तंत्र को पैसा नहीं दे सकती इसलिए यह गड़बड़ी है । इसलिए मैं यह चाहूंगा कि मंत्री जी इसकी जांच करवायें कि काम की गुणवता के अनुसार उन दोनों के कामों में क्या फर्क पड़ता है ?

श्री सभापति : इस पर तो गौर करने का है जवाब मैं समझता हूं कोई नहीं है । उन्होंने कहा है कि मशीन का इस्तेमाल ज्यादा होना चाहिए ।

श्री रामनिवास मिर्धा : मेरा उत्तर यह है कि जहां तक यह संभव होता है मशीन का उपयोग किया जाता है। जहां पर उचित समझा जाता है कांट्रेक्ट लेबर से काम लिया जाता है। माननीय सदस्य का यह कहना है कि किसी और वजह से किया जाता है, यह ठीक नहीं है।

श्री लक्ष्मी नारायण : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि सप्लीमेंट्री ड्रेन बनने में देर इसलिए लग रही है कि पहले इसको आबादी के बाहर निकालने की योजना थी लेकिन अब इसको आबादी के बीच में से निकाला जा रहा है?

श्री राम निवास मिर्धा : ड्रेन कहां बनेगा, कितना बड़ा बनेगा, इसका निर्णय तो 1979 में हो चुका था, और दिल्ली प्रशासन को उसी योजना के आधार पर कार्य करना चाहिए। लेकिन कई वजूहात है कि वह नहीं कर पा रहे हैं...

श्री. लक्ष्मी नारायण : मैंने जो प्रश्न पूछा उसका जवाब मिनिस्टर साहब ने नहीं दिया। पहले जहां से निकालने की योजना थी, अब उस ड्रेन को वहां से निकालकर दूसरी जगह से निकाला जा रहा है इसके बारे में बताइये। It was originally out of the populated area; now it has been shifted to the populated area.

SHRI RAM NIWAS MIRDHA: It is not correct that it has been shifted. Only in ihe Rohini Complex, ths Administration itself suggested certain changes which were considered. But the basic flow of the suplementary drain has to fellow certain levels and. therefore, it is a :echnical proposition as to where and how the drain will go. Possibly, the people do not want it to go through their area? and that is why the Delhi Administration is facing difficulty as to how it should be constructed. My request to the hon. Members from Delh is to impress upon the Administration that it is a very serious problem and seeing our experience in 1977 floods, something very urgently has to be done so that the same situation may not be repeated.

श्री लक्ष्मी नारायण : 1977 में तो जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी।... (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Next question.

Procurement of substandard foodgrains

*44. SHRI SHRIDHAR WASUDEO DHABE:f

SHRI SURESH KALMADI:

Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is a lot of pilferage of foodgrains procured by the Food Corporation of India during transit, if so, what are the details theteof for the last three years;

(b) whether it is also a fact that there is inadequate storage facility, if so, the extent of losses of foodgrains on that account during the last three years;

(c) whether it is a fact that foodgrains below the specifications prescribed by the Food and Civil Supplies Ministry are procured by the F.C.T., if so, what are the details thereof for the last three years; and

(d) what action Government are taking in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI BHAGWAT JHA

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Shridhar Wasudeo Dhabe.